







सम्पादकीय

# क्या सदन में ज्यादातर समय हंगामा ही होता रहेगा?

संसद के शातकालान सत्र का पहला दिन हगाम का भट्ट चढ़ गया। अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी अधियोजकों के रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग, मणिपुर में ताजा हिंसा, दिल्ली में बढ़ता वायु प्रदूषण और संभल में हुई हिंसा के मुद्दे पर चर्चा के लिए अडे विषयक ने भारी हंगामा किया। इस कारण दोनों सदनों की कार्यवाही एक-एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल संसद का कोई भी सत्र हो, उसकी शुरुआत हंगामे से होना एक प्रत्यंगा का रूप ले चुका है।

संसद के शातकालीन सत्र का पहला दिन हांगमा का भट चढ़ गया। अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों के रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग, मणिपुर में ताजा हिंसा, दिल्ली में बढ़ता बायू प्रदूषण और संभल में हुई हिंसा के मुद्दे पर चर्चा के लिए अडे विषय ने भारी हंगामा किया। इस कारण दोनों संसदों की कार्यवाही एक-एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल संसद का कोई भी सत्र हो, उसकी शुरुआत हंगामे से होना एक परंपरा का रूप ले चुका है। यह एक खबराख परंपरा है, लेकिन यह इसके बाद भी जारी है कि इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होता-उस विषय को भी नहीं, जो हंगामा करता है। विडंबना यह है कि वह हंगामे को अपनी जीत की तरह प्रस्तुत करता है। संसद में इस या उस मुद्दे के बहाने हंगामा करना एक राजनीतिक स्वभाव बन गया है। जब जो दल विषय में होता है, वह हंगामा करना पसंद करता है और वह भी तब, जब वह सत्ता में रहते समय हंगामे से त्रस्त हो चुका होता है। इस पर हैरानी नहीं कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन दोनों संसदों में हंगामा हुआ। विषय को हंगामा मचाने की इतनी जल्दी थी कि दिवंगत संसदों को श्रद्धांजलि देने के तुरंत बाद ही हंगामा किया जाने लगा। क्या इसलिए कि उसकी पहली प्राथमिकता हंगामा करना ही था? संसद के आने वाले दिन भी हंगामे भरे हों तो आशर्च्य नहीं, क्योंकि विषय ने पहले ही संकेत दे दिया था कि वह इन-इन मुद्दों को संसद में उड़ाएगा। विषय यदा-कदा अपने हिसाब से ज्वलंत मुद्दों को उठाता है, लेकिन उन पर सार्थक बहस करने और सरकार से जवाब मांगने के बजाय उसकी दिलचस्पी इसमें अधिक होती है कि संसद चलने न पाए। आम तौर पर विषय संसद में सरकार को घेरने के लिए मुद्दों का चयन खुद नहीं करता। वह उन मुद्दों को लेकर आगे आ जाता है, जो संसद सत्र के पहले से ही चर्चा में आ गए होते हैं। यह पहले से तय था कि मणिपुर और अडानी प्रकरण के साथ संभल का मामला भी विषय की कार्यसूची में आ जाएगा। ऐसे मामले उसकी कार्यसूची में होने ही चाहिए, लेकिन क्या उसके लिए यह भी आवश्यक नहीं कि वह अपने स्तर पर जनता से जुड़े कुछ मुद्दों का चयन करे और इसके लिए प्रयत्न करे कि सरकार उन पर जवाब दे? शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरीकरण समेत न जाने कितने ऐसे विषय हैं, जिन पर संसद में व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए। पता नहीं क्यों विषय इन विषयों पर संसद में चर्चा के लिए गंभीर नहीं दिखता? विषय हंगामा कर संसद को बाधित करते रह सकता है, लेकिन वह ऐसा करके जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। जनता हंगामा नहीं, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सरकार का जवाब चाहती है। बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में हजारों हजार करोड़ रुपये का खर्च क्या महज इसलिए किया जाता है कि सदन में विधाई कामकाज या कहें कि सकारात्मक नीति निर्धारण पर बहस बहुत कम और अराजकता बहुत ज्यादा होती है। राज्यसभा के लिए चुनाव सीधा नहीं होता, लेकिन उसमें भी आम आदमी का पैसा खर्च तो होता ही है। हालांकि लोकसभा चुनाव के मुकाबले बहुत कम। इसके अलावा सांसदों के वेतन, भत्ते, बाद में पेंशन और सांसदों के आवासों के खर-खाव और दूसरी सुख-सुविधाओं, चुनाव आयोग (राज्यों में भी) के संचालन में होने वाला सामान्य खर्च, इत्यादि पर आने वाली लागत भी जोड़ दी जाएं, तो आंकड़ा क्या होगा, आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के संचालन पर आने वाले खर्च, संसदीय कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन, संसदीय कार्यवाही के प्रकाशन, प्रसारण, संग्रहण, संसदीय समितियों की कार्यवाही, संसद भवन और संसद से जुड़ी दूसरी बहुत सी इमारतों के खर-खाव, संसद की सुरक्षा इत्यादि के खर्च के बारे में क्या आप अनुमान भी लगा सकते हैं? क्या देश के सरकारी खजाने पर लाखों करोड़ रुपये का इतना बड़ा बोझ सिर्फ इसलिए डाला रहा है कि संसद को हर समय युद्ध के मैदान में ही तब्दील रखा जाए? साथ ही आप चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जेब से होने वाला निजी खर्च और पार्टीयों के संस्थान खर्च पर, चुनाव से इतर कार्यक्रमों और दूसरी गतिविधियों पर भी अच्छी-खासी रकम खर्च की जाती है।

# संभल की दुर्भायपूर्ण घटना से उपजे जटिल सवाल

संभल की स्थानीय अदालत ने उस याचिका पर जामा मस्तिष्क के सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि मुगल बाटशाही बाबर ने इस मस्तिष्क का निर्माण एक मंदिर के स्थान पर किया था। स्थानीय अदालत के आदेश पर इसी मंगलवार को जब प्रारम्भिक सर्वे किया गया था तब भी इलाके में तनाव फैला था, लेकिन उसे दूर कर लिया गया था। समझना कठिन है कि गत दिवस सर्वे के दौरान ऐसे प्रायस्य तर्जों नहीं किए गए जिससे

दौरान ऐसे प्रयास क्यों नहीं किए गए जिससे  
किसी तरह की अत्यवस्था और अशांति न  
फैलने पाए।

४८५

बार फिर एक संप्रदाय विशेष के लोगों ने जो हिंसा, नफरत एवं द्वेष को हथियार बनाकर अशांति फैलाई, वह भारत की एकता, अखंडता एवं भाईचारे की संस्कृति को क्षति पहुँचाने का माध्यम बनी है। स्थानीय अदालत के आदेश पर एक



था। अदालत के आदेश की अवहेलना करने के लिए हिंसा क

सहारा लेने का कहीं कोई औचित्य नहीं और तब तो बिलकुल भी नहीं जब निचली अदालत के किसी फैसले के खिलाफ ऊंची अदालतों में जाने का रास्ता खुला हो। यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या कुछ गजनीतिक दल एवं संप्रदाय विशेष के लोग किसी भी बहाने भड़कने और हिंसा करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं? वास्तव में जैसे यह एक सवाल है कि क्या भारतीय संस्कृति के अस्तित्व एवं अस्मिता से जुड़े इन धार्मिक स्थलों के नाम पर पश्चात, तोड़फोड़ और आगजनी करना जरूरी समझ लिया गया है? इन प्रश्नों पर संकीर्ण धार्मिकता से परे होकर गंभीरता के साथ विचार होना चाहिए। इसी तरह पुलिस प्रशासन को भी यह देखना होगा कि वैमनस्य बढ़ाने वाली घटनाएं क्यों बढ़ती चली जा रही हैं?

यह सही है कि 1991 का पूजा स्थल अधिनियम किसी धार्मिक स्थल में बदलाव का निषेध करता है, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह अधिनियम ऐसे किसी स्थल के सर्वेक्षण की अनुमति भी प्रदान करता है और इसी कारण वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण हुआ और धार में भोजशाला परिसर का भी। मथुरा में ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। मंदिर-मस्जिद के विवाद नए नहीं हैं। इन विवादों को सुलझाने की आवश्यकता है।

इसका एक तरीका न्यायपालिका का सहारा लेना है और दूसरा जापान आज अपनी जीवन शैली को बदल कर उत्कृष्ट उत्पादन का प्रतीक बन विश्वविद्यालय हो गया। यह सार्वीय जीवन शैर्लॉक की पवित्रता का प्रतीक है। इसी तरह भारत भी आज विश्वविद्यालय होने की दिशा में अग्रसर हो रहा है, तो उसकी बढ़ती साख एवं समझ को खण्डित करने वाली शक्तियों का सावधान करना ही होगा। भारत जैसी माटी में जन्म लेना बड़ी मुश्किल से मिलता है। विश्व बंधुत्व एवं वसुधैव कुटुम्बकम् की विचारधारा वाला यह राष्ट्र विभिन्न संस्कृतियों एवं सम्प्रदायों को अपने में समेटे हैं तो यह यहां के बहुसंख्यक समुदाय की उदार सोच का ही परिणाम रहा है, इसी बहुसंख्यक हिन्दू समुदाय को आखिर कब तक कमजोर किया जाता रहेगा? क्यों किया जायेगा? कल पर कुछ मत छोड़िए। कल जो बीत गया और कल जो आने वाला है— दोनों ही हमारी पीठ के समान हैं, जिसे हम देख नहीं सकते। आज हमारी हथेती है, जिसकी रेखाओं को हम देख सकते हैं। अब हथेतृ की रेखाओं को कमजोर करने एवं उसे लहूलुहान होते हुए नहीं देखा जा सकता? एक सम्प्रदाय विशेष के हिंसक हमलों ने आज तेजी के साथ हिंसा, असहिष्णुता, नफरत, बिखराव औं और धृणा की साप्रदायिक जीवन शैली का रूप ग्रहण कर लिया है। यह खतरनाक स्थिति है, कारण सबको अपनी-अपर्ना-पहचान समाप्त होने का खतरा दिख रहा है। भारत मुस्लिम सम्प्रदायवाद से आतंकित रहा है। आवश्यकता है धर्म के

आपसी सहमति से विवाद को हल करना। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि जहां भी ऐसे विवाद हैं, उन्हें दोनों सम्मदाय आपस में मिल-बैठकर हल करें। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि समाज में सद्गुर, सौहार्द एवं शांति बनी रहेगी। यह समझा जाना चाहिए कि इन दोनों उपायों के अतिरिक्त हिंसा एवं नफरत कोई उपाय नहीं है। इसी के साथ यह भी समझना होगा कि देश को अतीत से अधिक भविष्य की ओर देखने और मंदिर-मस्जिद विवादों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। इससे इन्कार नहीं कि विदेशी आक्रमणकारियों ने अनगिनत मंदिरों का ध्वंस किया। अतीत में हुए इन ज्यादितयों, अत्याचारों एवं विध्वंस घटनाक्रमों को सुधारने की संभावनाएं किसी भी दृष्टि से गलत नहीं कही जा सकती। देश का चरित्र बनाना है तथा स्वस्थ, सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण समाज की रचना करनी है तो हमें एक ऐसी आचार संहिता को स्वीकार करना होगा जो जीवन में पवित्रता दे। राष्ट्रीय प्रेम व स्वस्थ समाज की रचना की दृष्टि दे एवं कदाचार-संकीर्णता-कटूरता के इस अंधेरे कुएं से निकाले। बिना इसके देश का विकास और भौतिक उपलब्धियां बेमानी हैं। व्यक्ति, परिवार और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे इरादों की शुद्धता महत्व रखती है, प्रतिष्ठित करने के बहाने राजनीति का खेल न खेला जाए। धर्म और सम्प्रदाय के भेद को ग़म्मद् न करें। धर्म सम्प्रदाय से ऊपर है। धर्म में धार्मिकता आये, कटूरता न आये। राजनीति में सम्प्रदाय न आये, नैतिकता आए, आदर्श आए, श्रेष्ठ मूल्य आएँ, सहिष्णुता आये, सह-अस्तित्व के प्राचीन मूल्य एवं जीवनशैली आये। अतः सम्प्रदायवाद से ऊपर उठकर सार्वभौमिक धर्म का साक्षात्कार ही हममें नवीन आत्मविश्वास, सशक्ति भारत-विकासित भारत का संचार करेगा। उपनिषदों में कहा गया है कि सभी मनुष्य सुखी हों, सभी भयमुक्त हों, सर्भं एक-दूसरे को भाई समान समझें। यह भारतीय धर्म चिन्तन का निचोड़ है और यही हिन्दू धर्म का निचोड़ है। जहां विश्व एक ही नीड़-सा लागे। भारत में हिन्दू-मुस्लिम हित परस्पर टकरारहे हैं, इसलिए साम्प्रदायिकता बढ़ रही है। धार्मिकता नष्ट हो रही है। साम्प्रदायिकता का जन्म अनेक जटिल तत्वों से जुड़ा है- आर्थिक, धार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक। इसमें मनोवैज्ञानिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन दिशासूचक बने। गिरजे पलतगा दिशा-सूचक नहीं, वह तो जिधर की हवा होती है उंधर ही धूम जाता है। कुतुबनुमा बने, जो हर स्थिति में सही दिशा बताता है।

# ਮਾਸੂਮਾ ਕਿਲੇ ਲਾਪਤਾਗਿੰਜ ਬਨਤੀ ਦੁਨਿਆ

दुनिया आधुनिक संचार माध्यमों और परिवहन साधनों की बढ़ालत ग्लोबल विलेज में तबदील हो गई है। दूसरी तरफ इसी दुनिया में भारत से हर दिन हजारों की संख्या में बच्चे लापता हो रहे हैं। ऐसे दौर में जब हर कहीं पलक झपकते सूचना पहुंच जाती हो, जब हर कहीं कैमरे की पहुंच हो गई हो तो हर साल देशभर से लगभग 80,000 से ज्यादा बच्चों के गायब होने का क्या मतलब है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के दिसंबर 2023 में जारी आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 में 83,350 बच्चे गायब हुए, जिनमें 20,380 लड़के व 62,946 लड़कियां और 24 ट्रांसजेंडर थे। इनमें ज्यादातर तलाश थी लिए गये लेकिन 2781 बच्चे हमेशा हमेशा के लिए ओझल हो गये। जबकि इसके पहले एनसीआरबी ने जो डाटा 2022 में पेश किया था, उसमें लापता हुए बच्चों की संख्या 76,069 थी। मतलब साफ है कि अगले एक साल में लापता हुए बच्चों की संख्या में तकरीबन 6000 की बढ़ोतरी हो गई। जबकि 2021 में गायब होने वाले बच्चों की संख्या सिर्फ 33,650 थी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि बच्चों के गायब होने की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो रही है। सवाल है एक तरफ जहां बच्चों की सुरक्षा के लिए हर साल नई से नई बातें कहीं जाती हैं, कसमें खायी जाती हैं और आधुनिक से आधुनिक उपकरण लगाकर सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। फिर भी मासूमों के गायब होने के सिलसिले में जरा भी कमी आने को बजाय बढ़ोतरी क्यों रही है? अगर इस आंकड़ों की जगह उन गैरसरकारी संस्थाओं पर यकीन करें, जो बच्चों के लापता होने की समस्या में काम करती हैं, तो बच्चों के गायब होने की वास्तविक संख्या इससे ज्यादा है। इनके मुताबिक तो हर साल 80-85 हजार नहीं बल्कि कई लाख बच्चे गायब हो रहे हैं। यही वजह है कि आज देश में हर एक मिनट में कम से कम दो बच्चे गायब हो रहे हैं। घर से बछुड़कर आखिर ये मासूम कहां चले जाते हैं? क्योंकि जो बच्चे अगले एक महीने तक नहीं मिलते, घरों से गायब होने वाले ऐसे बच्चों के घर वापस न आने की आशंका करीब सौ फीसदी हो जाती है। जो बच्चे गायब होने के बावजूद मिल जाते हैं, उनके बारे में तो हम थोड़ा-बहुत जानते भी होते हैं किंतु इन्हें कौन और कैसे बहला-फुसलाकर ले गया था। लेकिन जो बच्चे कभी लौटकर आये ही नहीं उनके बारे में मां-बाप कुछ भी नहीं जानते। संचार के साधनों के बावजूद एक-देह फीसदी बच्चे गायब होने के बाद कभी वापस नहीं आते हालांकि अपराधियों की धड़पकड़ में हाल के सालों में जिआफा हुआ है पुलिस के पास आज पहले बेतहत मुकाबले जांच पड़ताल के संसाधन हैं, इसके बाद भी गायब बच्चों की एक तय संख्या लौटकर घर नहीं आती, तो आखिर उनका होता क्या है? उनका कोई सुराग क्यों नहीं मिलता? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया के डाटा विश्लेषण के मुताबिक हर दिन हजारों की संख्या में गायब होने वाले बच्चों में से बहुत मामूली संख्या में ही बच्चे लौटकर आ पाते हैं।

में वे दोनों मिले। ये महानुभाव लंबे समय तक एक-दूसरे के विपरीत गठबंधनों की केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। दोनों ने पूछा, महाराष्ट्र के चुनावों में क्या होने वाला है? मैंने विनम्रतापूर्वक प्रतिप्रश्न किया—आप बताइए, आप तो राजनीति के अंदरूनी तंत्र का हिस्सा हैं। पहले सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य को सुनिए। उहाँने कहा—

हम ही सरकार बनाएंगे, क्योंकि मोदीजी के पास कोई न कोई सिद्धि जरूर है। वे हर मुसीबत से निकल आते हैं। यह चुनाव उनकी सिद्धि का अगला चरण साबित होगा। विपक्षी टोली के सदस्य का जवाब था- भाई, मैंने तो हरियाणा के बाद आकलन ही छोड़ दिया है। भाजपा वाले आखिरी तीन दिनों में पता नहीं कौन सा जादू करते हैं कि सारा किया-धरा चौपट हो जाता है। संयोगवश, वह उस दिन मुंबई से लंबी चुनाव-चर्चाएं करके लौटे थे। पांच दशक से अधिक लंबी

विपक्षी टोले के नेता का जवाब भी यही दर्शाता है कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक विजय हासिल करने योग्य आत्मविश्वास नहीं संजो पा रहे हैं।  
महाराष्ट्र का यह विजयनामा यूं ही नहीं लिखा गया। जीत की राह वार्कर्इ कठिन थी। जब से एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने अपने-अपने मूल दलों से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, तभी से माना जाता था कि वे जनता की नजर में खलनायक साबित होंगे। उद्घव ठाकरे और शरद पवार ने इस

संस्थासा पारा खल चुक इन  
पुरोधाओं के शब्दों पर गौर  
कीजिए- सिद्धि! जादू! क्या  
मतलब है इनका?

सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि का आशय  
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी  
दैवीय सिद्धि से नहीं, बल्कि  
अद्भुत सियासी कौशल और आम  
आदमी के मानस की समझ से  
था। इसी के चलते भारतीय  
जनता पार्टी के कार्यकर्ता मानते हैं  
कि किसी चुनाव में अगर हमारी  
सीटें कम रह जाएंगी, तो अगला  
चुनाव उसकी भरपाई कर देगा।

सहानुभूत तत्त्व का लाभ उठान  
की हर चंद्र कोशिश की, पर वे  
नाकाम साबित हुए। क्यों?  
लोकसभा चुनावों में सरकार के  
खिलाफ हुई मराठा लामबंदी को  
महायुति ने इस बार  
सफलतापूर्वक रोका। इसी के  
साथ अजित पवार को मुस्लिमों  
में पैठ बनाने के लिए प्रेरित किया  
गया। इससे आधाड़ी को  
सांघातिक आघात पहुंचा। चुनाव  
से चार महीने पूर्व लागू लाडकी  
बहिण योजना ने महिलाओं का  
मन मोह लिया। महिलाएं चुनाव-

ताकत जमाती जा रही है। झारखंड में इनका साथ हेमंत सोरेन को मिला। उन्होंने भी मंडलियां सम्मान योजना के जरिये आधी आबादी में दखल बनाई थी। इन चुनावों ने साबित कर दिया है कि जीत के लिए विरासत और सहानुभूति काफी नहीं होते। जमीन पर काम भी करना पड़ता है। महाराष्ट्र में भाजपा ने इस बारे

काई जोखिम मोल नहीं लिया। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में टिकट बंटवारे और सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे के जटिल कार्य को समझदारी और सावधानी के साथ सिरे तक पहुंचाया गया। नतीजा सामने है। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइकरेट अगर 89 फीसदी है, तो शिंदे 71 और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस 77 के साथ उसमें इजाफा कर रही है। परिणाम आने के बाद अब भले शिंदे, अजित पवार और फडणवीस के नाम मुख्यमंत्री पद के लिए उछाले जा रहे हैं, परं चुनाव तक वे इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर वाचाल न थे। इसके विपरीत महाविकास आघाड़ी में जितने बर्तन थे, उतनी ही ध्वनियां निकल रही थीं। यही वजह है कि उनका मतदाता उनसे छिटक गया। इस चुनाव में यह भी सबित हो गया कि दलबदल और भ्रष्टाचार बड़े मुद्दे नहीं रह बचे हैं, क्योंकि सभी पार्टियों में दलबदल थे। चुनाव से ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर महासचिव विनोद

लगे। सुप्रिया सुले और पटोले के कथित ऑडियो सामने आए। पुलिस और आयोग के दरवाजे खटक गए, पर कोई हलचल न हुई नहीं, चुनाव आयोग ने 18 तक 1,100 करोड़ रुपये शराब, ड्रग्स, आभूषण कीमती उपहार जब्त किए रिकॉर्डतोड आंकड़ा है। राजनीति में धन-बल और

अब प्रमुख तत्व के तौर पर चुके हैं। सवाल उठता है कि यह झारखंड में क्यों नहीं काम उठाया जाए? इसकी कई वजहें हैं। महाराष्ट्र भारतीय हाथों पर जितनी पार्टी उतने नेता नहीं थे। साथ ही यह ब्लॉक के अन्य घटक द्वारा हेमंत सोरेन के कद का कोई नहीं था। इससे भ्रम नहीं नहीं था। चुनाव से कुछ महीने पहले न गिरफ्तारी ने भी ऐंटी इनकार्पोरेशन को खत्म कर दिया। भ्रम जनता पार्टी ने यहां पर मरांडी की शैली में तोड़-फोड़ की, परंतु चंपाई संरेन वह नहीं कर सके, जो अजित या एकनाथ शिंदे ने फिर भाजपा ने इस बार बाबू मरांडी को आगे कर यह देने की कोशिश की किंतु आदिवासियों के साथ है, तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी उनकी गैर-मौजूदगी में कर सोरेन की कारगर सत्रिया मरांडी पर महंगी पड़ी। एक और। झारखंड के परिणाम साबित कर दिया है कि अधिसंघ्य हिंदीभाषी प्रदेश

जीतने की शक्ति गंवा रही है। वे किसी हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव का मार्ग प्रशस्त करती हैं, परंतु उसके निजी शक्ति छींजती जा रही है ज्ञारखंड के झटके के बावजूद यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी अब नए जौश-खोरोश के साथ अगले चुनावों की तैयारी करेगी। इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि एनडीए के सहयोगी

अब और सजीदगी से मोर सरकार का साथ देंगे। इसके प्रधानमंत्री को अपने कार्यक्रम तेजी से लागू करने में मद मिलेगी। यहाँ यह सवाल है कि उठता है कि एकनाथ शिंदे का क्या होगा? उन्होंने उद्घव व मुकाबले खुद को स्थापित अवश्य किया, पर बाला साहेब का स्वाभाविक उत्तराधिकार बनाना शेष है। अगर वह मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तो उन्होंने आने वाले दिनों में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है रही बात विपक्ष की, तो वह इस पटखनी के बाद धूल झाड़क यह कहते हुए खड़ा हो सकता कि लोकसभा के बाद हुए चरित्र विधानसभा चुनावों में दो हमेशा भी जीते। प्रियंका गांधी वाड़ा वायनाड से चुन ली गई हैं। क्या वह राहुल गांधी के साथ मिलकर कांग्रेस में नई स्फूर्ति का संचय कर सकेंगी? तय है, विपक्ष व झटका लगा है, पर उखड़ती सांसद सम्हालने का अवसर अभी उसके पास है। लोकतंत्र की यह तो खूबी है कि यहाँ हरेक के लिए हमेशा स्पेस बना रहता है।



## दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में NSUI की ऐतिहासिक जीत

कटनी ने आतिथबाजी और गिराई के साथ जश्न

सुनील यादव। सिटी चीफ कटनी, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में एनएसयूआई की प्रेसिडेंट पद जीत होने की खुशी में मध्यप्रदेश के कटनी जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शासकीय तिलक कालेज में आतिथबाजी और एक दूसरे को मिठाई बाट जश्न मनाया। NSUI KE पदाधिकारियों ने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में NSUI ने बड़ी जीत दर्ज की। NSUI ने प्रेजिडेंट और जॉड्ट एंसेट्री पर पद पर जीत हासिल की।



ABVP का चार साल का प्रेजिडेंट पद पर कब्जा खाम हुआ। 2017 के बाद NSUI की यह बड़ी वापसी है। कम बोटिंग के बावजूद NSUI ने जीत हासिल कर रखी।

## जनपद के सरकारी, अर्द्धसरकारी, नगर निकायों एवं शिक्षण संस्थानों में भव्य रूप से आयोजित हुआ संविधान दिवस

आयुक्त कार्यालय, कलेक्टर एवं विकास भवन में दिलाई गयी संविधान की शपथ

गौरव सिंधल। सिटी चीफ सहारनपुर, संविधान दिवस के अवसर पर राज्यमंत्री लोक निर्माण विभाग बृजेश सिंह की अध्यक्षता एवं विधायक नकुड़ मुकेश चौधरी, विधायक रामपुर मणिहाराज देवेन्द्र निम एवं जिलाधिकारी मनीष बंसल की उपस्थिति में कलेक्टर स्थित नवीन सभागार में संविधान दिवस का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर लोक भवन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया। राज्यमंत्री ने इस अवसर संविधान की प्रस्तावना की सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शपथ दिलाई। हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पर्क समाजवादी पर्याप्तिक लोकतंत्रमय गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नारिकों को सामाजिक, अर्थिक और राजनीतिक व्याय, विचार, अधिकारिक, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समांत्र प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली

बंधुता बढ़ावा के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवम्बर 1949 10 मिति मार्ग शीर्ष शुक्रवार समझी, संवत दो हजार छह विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने कहा कि हम आज से संविधान दिवस के अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा संविधान सर्वधर्म एवं सर्वसमाज को लेकर चलने वाला है। संविधान के माध्यम से ही देशवासियों को अधिकार एवं कर्तव्य मिले हुए हैं। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है। उन्होंने कहा कि संविधान का निर्माण करने वाले समस्त विभूतियों जिसमें सर्वप्रथम नाम डॉ भीमराव

देश बना है।



## इमरान मसूद को मिली नई जिम्मेदारी, दिल्ली में उम्मीदवारों की चयन समिति में मिली जगह

गौरव सिंधल। सिटी चीफ सहारनपुर, सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद को कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने महत्व देते हुए उन्हें दिल्ली में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन समिति में रखा गया है। सांसद इमरान मसूद ने



## शासकीय एकीकृत शाला माध्यमिक विद्यालय जाख में निशुल्क साइकिल वितरण का कार्यक्रम संपन्न

सुनोर नगर की 165 वीं विधानसभा के ग्राम पंचायत जाख में शासकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों को साइकिल वितरण कर रखा है। विद्यार्थियों ने साइकिल पाकर बहुत खुश हुए और साथ ही सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार हम गरीबों को इस तरह से खाल रखती है जैसे की मां अपने बच्चों का इस अवसर पर भाज्युमों जिला मंत्री लखन सेन किसान मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष बने सिंह यादव स्कूल स्टाफ दिनेश सर, बोहरा अब्दुल फिरोज, परिवार शर्मा शरीफ मंसूरी एवं साथ ही कई लोग ग्रामीण अंचल के भी लोग उपस्थित रहे।



भगवान दास बैरागी। सिटी चीफ शाजापुर, प्रधानमंत्री कालेज ऑफ एक्सीलेंस बीकैप्सेन गवर्नर्मेंट कालेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई तथा नेहरू युवा केंद्र शाजापुर के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में शपथ ग्रहण एवं निवध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ वीपी मीणा ने संविधान की शपथ दिलाई। वर्षीय रासेयों जिला संस्कार प्रो दृष्ट्यांकुमार यादव ने रासेयों स्वयंसेवकों तथा विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह

मौजुसिंह रहे तथा संत्वना पुरस्कार सुनन बैरागी को दिया गया। इस अवसर पर प्रो प्रकाश बफां, प्रो गरिमासिंह परिहार, रासेयों इकाई दलनायिका हर्षिता पाटीदार, दीपिका शर्मा, रीना पंवार, नेहा शर्मा, श्रीनाथ, अनिल शर्मा, रितेशकुमार वर्मा, रासेयों मिडिया प्रभारी पवन पुरी सहित रासेयों स्वयंसेवक एवं महाविद्यालय के विद्यार्थी भौजूद रहे। कार्यक्रम में शपथ के पश्चात रासेयों इकाई एंबेसेडर रवि कुमार के नेतृत्व में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें रासेयों स्वयंसेवक एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भारत का संविधान विषय पर भाषण दिए। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम शिवम् परिहार, द्वितीय लक्ष्मी पुष्पद एवं तृतीय विद्यालय की रानू

सक्सेना ने संविधान उद्देशिका का वाचन किया तथा वरिष्ठ शिक्षिका शैफाली जीवों द्वारा संविधान दिवस पर विद्यार्थियों को संविधान की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई गई। शिक्षक हेमंत सक्सेना ने संविधान सभा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। शिक्षक ईश्वरलाल मालवीय ने बताया कि भारतीय संविधान दृनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसे तैयार करने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। शिक्षकों द्वारा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से संविधान के उद्देश्यों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर तबस्सुम शाह, ईश्वरलाल मालवीय, सीमा सोनगारा, दिलीप जायसवाल, हेमंत सक्सेना, अरुणा कराडा, रुचि नागर, शैफाली

## मिड डे मील में अनियमितताओं के खिलाफ सपा का अनोखा प्रदर्शन

दोल-दप्ती के साथ कलेक्टरेट पहुंचे पदाधिकारी, मिड डे मील टेंडर पर उठाए सवा

सुनील यादव। सिटी चीफ

कटनी, कटनी कलेक्टरेट कार्यालय में आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अपने दो अन्य पदाधिकारियों के साथ दोल डप्टी और दप्ती बजाते हुए कलेक्टरेट कार्यालय पहुंच अनोखा प्रदर्शन किया। ये सभी मिड डे मील के संचालक के खिलाफ किया प्रदर्शन कर रहे हैं, इंदौर की आकांक्षा समूह को मिड डे मील का टेंडर दिए जाने से नाशा रहा है। इनका आरोप है कि यह संस्था ऐसे संस्था को टेंडर दिया है जो जाती विवाही नहीं हुई।



पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि मिड डे मील के संचालक के खिलाफ यह अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है।

जिले में इंदौर की आकांक्षा समूह को मिड डे मील का टेंडर दिया गया है लेकिन इस फर्म में कटनी प्रदर्शन किया जा रहा है।

दिया है जो कटनी जिले के बच्चों को भोजन को गुणवत्ता खराब भोजन दे रहा है। और अधिकारी हैं कि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

## पॉलीथिन खाने से हो रही गौवंशों की मौत कलेक्टर कार्यालय पहुंचे गौशाला संचालक

भगवान दास बैरागी। सिटी चीफ

शाजापुर, नगरपालिका के द्वारा गौशाला के समीप फैक्ट्री जा रही पॉलीथिन से गांवों के जीवन पर संकट खड़ा हो गया है और इसी परेशानी से परेशान होकर गौशाला संचालकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है। मंगलवार को ग्राम भीलवाड़िया के द्वाराकाशी ओम शर्मिंग गौशाला के संचालक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और शिकायत कर बताया कि गौशाला के समीप ही शाजापुर नगरपालिका के द्वारा भीलवाड़िया के गौशाला में संकट खड़ा हो रहा है। इसके बाद गौशाला के गौवंशों में बोल खुले में कर्चरा फैक्ट्री जा रहा है। उक्त कर्चरे में पॉलीथिन की मात्रा अधिक है जिसकी वजह से गौशाला के गोवंश और अन्य मवेशी पॉलीथिन खाकर मृत हो रहे हैं। इन्होंने गौवंशों की जान जा चुकी है, जिसकी कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन



कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गौशाला संचालकों की मांग है कि कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर गौवंशों की मांग की गई है। गौशाला संचालकों की जान जा चुकी है, जिसकी कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन

निकलने वाला कलेक्टर नगरपालिका के द्वारा भीलवाड़िया क्षेत्र में फैक्ट्री जा रहा है, जिसको लेकर गौशाला संचालकों का आरोप है कि नपा कलेक्टर खुले में फैक्ट्री है जिसमें पड़ी पॉलीथिन खाने से गौवंशों की म



# अमेरिका में 2003 के बम धमाके का आरोपी 21 साल बाद ब्रिटेन से हुआ गिरफ्तार



इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका में 2003 में कैलिफोर्निया की एक बायोटेक कंपनी में हुए बम धमाके के आरोपी डेनियल आड्रेस सैन डिएगो को 21 साल बाद ब्रिटेन के वेल्स से गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी अमेरिकी संघीय जांच एजेंसी एफबीआई ने दी है। आरोपी डेनियल सैन डिएगो एक पशु अधिकार कार्यकर्ता था जिसने बायोटेक कंपनी में बम धमाका किया था।

## कैलिफोर्निया के बम धमाके का मामला

सैन डिएगो पर आरोप है कि उसने अगस्त 2003 में कैलिफोर्निया के ओकलैंड के पास एक बायोटेक फर्म चिरेन

इं में दो बम लगाए थे। हालांकि दूसरे बम को जांच अधिकारियों ने निष्क्रिय कर दिया था। इसके बाद सैन डिएगो ने एक महीने बाद कैलिफोर्निया की एक और कंपनी में तीसरा बम लगाया लेकिन इन धमाकों के बीची को चोट नहीं आई थी। आरोपी का गिरफ्तारी और अभियोजन

एफबीआई ने बताया कि डेनियल सैन डिएगो को ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी आतंकवाद नियोधक पुलिस और उत्तरी वेल्स पुलिस ने संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी एफबीआई के साथ समन्वय में हुई। डिएगो पर 2009 में आरोप तय किया गया

था और वह तब से फरार था। क्या थे धमाकों के पीछे के कारण?

सैन डिएगो और उसके सहयोगियों ने ये बम धमाके एक पशु अधिकार संगठन के तहत रिवोल्यूशनरी सेल्स के लिए कर्भी हार नहीं मानती। उन्होंने कहा, हमारे देश में अपनी बात खेने का सही तरीका है। लेकिन हिंसा करना और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सही तरीका नहीं है।

अंत में कहा जा सकता है कि सैन डिएगो की गिरफ्तारी से यह भी साफ हो गया है कि अमेरिकी कानून व्यवस्था किसी भी संदिध के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई कम्पर नहीं छोड़ती चाहे वह कितने साल भी छिपा रहे।

# हिंडन नदी पुल पर बड़ा ट्रक हादसा, 2 की मौत



नेशनल डेस्क. बुधवार तड़के मुरादाबाद के पास हिंडन नदी के पुल पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ट्रक नदी में गिर गया। इस हादसे में ट्रक में सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य को पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सुकूशल बाहर निकाल लिया।

पुलिस अधिकारी सीओ गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि पंजाब के तुधियाना से एक ट्रक में ईंट भट्ठे में इस्रेमाल होने वाली मिट्टी मुरादाबाद ले जाई जा रही थी। ट्रक

बुढाना से होते हुए मुजफ्फरनगर की ओर जा रहा था। बुधवार तड़के करीब तीन बजे ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिर गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और बचाव कार्य शुरू किया। घटों की मेहनत के बाद स्थानीय लोगों और हाइड्रा क्रेन की मदद से ट्रक को नदी से बाहर निकाला गया। इस हादसे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने जाम की स्थिति को नियंत्रित किया और यातायात को सामान्य किया।

## आजमगढ़ में 190 करोड़ की ठगी का खुलासा

# 11 साइबर अपराधी विदेशी कनेक्शन से संचालित कर रहे थे ठगी का नेटवर्क

आजमगढ़. उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले की पुलिस ने मंगलवार को करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाल किया है। पुलिस ने 1 अरब 90 करोड़ रुपए के ठगों का खुलासा किया है। इस मामले में कुल 169 बैंक खातों में लागांग 2 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं। इसके अलावा 13 लाख 40 हजार रुपए नगद, 51 मोबाइल फोन, 6 लैपटॉप, 61 एटीएम कार्ड, 56 बैंक पासबुक, 19 सिम कार्ड, 7 चेकबुक, तीन आधार कार्ड, और एक जियो फाइबर राउटर भी बरामद किए हैं। इस मामले में आजमगढ़ पुलिस ने 11 अरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबकि 2 अरोपी फरार हैं। पुलिस टीम ने मुख्यकारी हेमराज मीना ने पत्रकारों को बताया है कि वे आजमगढ़

गिरफ्तार चलाए गए विशेष अधियान के तहत 25 नवंबर को थाना साइबर क्राइम की पुलिस टीम ने रेडी अना, लॉट्स और महादेव जैसे प्रतिवर्धित ऑनलाइन एप के जरिए ठगों करने वाले इस गैंग का पदार्थकाश किया। गैंग सोसाल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्ट्राम, व्हाट्सएप, मेटा और टेलीग्राम पर विज्ञप्ति देकर लोगों को अपने जांसंग में फँसाता था। गैंग के पीड़ितों को पैसे देगुने या तिगुने करने का लालच देकर उनकी लालचिन आईडी बनाता और अॉनलाइन गेम्स के जरिए उनके खातों से पैसे निकालकर फर्जी खातों में ट्रांसफर करता था। पीड़ितों की आईडी ब्लॉक कर दी जाती थी। पुलिस टीम ने पुलिस को पूछताल में बताया कि वे आजमगढ़

गिरफ्तार भी रहे थे, जिनमें कुल 13 सदस्य सक्रिय रूप से कार्यरत थे। ये लोग सरकार द्वारा प्रतिवर्धित एप का उपयोग कर रही करते थे। क्लासिक गुप्त के जरिए योग्यों से संपर्क किया जाता था। गैंग द्वारा अर्जित धनरुप के फर्जी खातों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझेदारों के साथ बाटा जाता था। गिरफ्तार अरोपियों में राम सिंह (28), संदीप यादव (25), विशालदीप (22), अजय कुमार पाल (25), आकाश यादव (24), पंकज कुमार पुष्पांय (26), प्रदीप शांतिया (22), विकास यादव (19), आनन्दी कुमार यादव (24), पीड़ित उमर बेग (21) और अमित गुप्ता शामिल हैं। पुलिस विनय यादव और सौरभ नामक ठगी की तलाश कर रही है।

में दो यूनिट चला रहे थे, जिनमें कुल 39.43 फीसदी और 48.14 फीसदी वोट मिले हैं। एस.सी.-आरक्षित सीटों किसे क्या हुआ है? एस.सी.-आरक्षित सीटों पर जीत के लिए एरीना राजनीति के अधियान ने अपने खारेब द्रवदेशन से महत्वपूर्ण वापसी भी की है। राज्य की कम से कम 15 फीसदी वाली दिलित अवादी वाली 67 सामान्य सीटों में भाजपा ने अपने 42 सीटों पर जीत की है। जबकि महायुति और प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी द्वारा दिलित, आदिवासी और ओ.वी.सी.सी. समुदायों को एकजुट करने का एक है तो जीत के लिए एस.सी.-आरक्षित सीटों से 3 कांग्रेस, 2-2 सेना (यू.बी.टी.) और शरद पवार की एन.सी.पी. की 2 सीटें पर जीत की है। एस.सी.-आरक्षित सीटों पर जीत के लिए एरीना राजनीति के अधियान ने अपने खारेब द्रवदेशन से 32 सीटों पर जीत की है। एस.सी.-आरक्षित सीटों पर जीत के लिए एरीना राजनीति के अधियान ने अपने 42 सीटों पर जीत की है। जबकि महायुति और प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी द्वारा दिलित, आदिवासी और ओ.वी.सी.सी. समुदायों को एकजुट करने का एक है तो जीत के लिए एस.सी.-आरक्षित सीटों से 3 कांग्रेस, 2-2 सेना (यू.बी.टी.) और शरद पवार की एन.सी.पी. की 2 सीटें पर जीत की है। एस.सी.-आरक्षित सीटों पर जीत के लिए एरीना राजनीति के अधियान ने अपने 42 सीटों पर जीत की है। जबकि महायुति और प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी द्वारा दिलित, आदिवासी और ओ.वी.सी.सी. समुदायों को एकजुट करने का एक है तो जीत के लिए एस.सी.-आरक्षित सीटों से 3 कांग्रेस, 2-2 सेना (यू.बी.टी.) और शरद पवार की एन.सी.पी. की 2 सीटें पर जीत की है। एस.सी.-आरक्षित सीटों पर जीत के लिए एरीना राजनीति के अधियान ने अपने 42 सीटों पर जीत की है। जबकि महायुति और प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी द्वारा दिलित, आदिवासी और ओ.वी.सी.सी. समुदायों को एकजुट करने का एक है तो जीत के लिए एस.सी.-आरक्षित सीटों से 3 कांग्रेस, 2-2 सेना (यू.बी.टी.) और शरद पवार की एन.सी.पी. की 2 सीटें पर जीत की है। एस.सी.-आरक्षित सीटों पर जीत के लिए एरीना राजनीति के अधियान ने अपने 42 सीटों पर जीत की है। जबकि महायुति और प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी द्वारा दिलित, आदिवासी और ओ.वी.सी.सी. समुदायों को एकजुट करने का एक है तो जीत के लिए एस.सी.-आरक्षित सीटों से 3 कांग्रेस, 2-2 सेना (यू.बी.टी.) और शरद पवार की एन.सी.पी. की 2 सीटें पर जीत की है। एस.सी.-आरक्षित सीटों पर जीत के लिए एरीना राजनीति के अधियान ने अपने 42 सीटों पर जीत की है। जबकि महायुति और प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी द्वारा दिलित, आदिवासी और ओ.वी.सी.सी. समुदायों को एकजुट करने का एक है तो जीत के लिए एस.सी.-आरक्षित सीटों से 3 कांग्रेस, 2-2 सेना (यू.बी.टी.) और शरद पवार की एन.सी.पी. की 2 सीटें पर जीत की है। एस.सी.-आरक्षित सीटों पर जीत के लिए एरीना राजनीति के अधियान ने अपने 42 सीटों पर जीत की है। जबकि महायुति और प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी द्वारा दिलित, आदिवासी और ओ.वी.सी.सी. समुदायों को एकजुट करने का एक है तो जीत के लिए एस.सी.-आरक्षित सीटों से 3 कांग्रेस, 2-2 सेना (यू.बी.टी.) और शरद पवार की एन.सी.पी. की 2 सीटें पर जीत की है। एस.सी.-आरक्षित सीटों पर जीत के लिए एरीना राजनीति के अधियान ने अपने 42 सीटों पर जीत की है। जबकि महायुति और प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी द्वारा दिलित, आदिवासी और ओ.वी.सी.सी. समुदायों को एकजुट करने का एक है तो जीत के लिए एस.सी.-आरक्षित सीटों से 3 कांग्रेस, 2-2 सेना (यू.बी.टी.) और शरद पवार की एन.सी.पी. की 2 सीटें पर जीत की है। एस.सी.-आरक्षित सीटों पर जीत के लिए एरीना राजनीति के अधियान ने अपने 42 सीटों पर जीत की है। जबकि महायुति और प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी द्वारा दिलित, आदिवासी और ओ.वी.सी.सी. समुदायों को एकजुट करने का एक है तो जीत के लिए एस.सी.-आरक्षित सीटों से 3 कांग्रेस, 2-2 सेना (यू.बी.टी